



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 3, 2006 (फाल्गुन 6, 1927)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2006 (PHALGUNA 6, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	185	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	171	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	209	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संच लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों, द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	185	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	171	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	209	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	551
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	81
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	241
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	83
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2006

संकल्प

सं. फा. 4(1)/2004-हिन्दी--दिनांक 23 दिसम्बर 2005 अपराह्न से लोक सभा के सदस्य नहीं रहने के फलस्वरूप, श्री मनोज कुमार दिनांक 23 दिसम्बर 2005 अपराह्न से संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं रहे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी. गोपालाकृष्णन
संयुक्त सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2006

संकल्प

सं. 5(1)/2005-चमड़ा--चमड़ा उद्योग अपनी पर्याप्त निर्यात आय, रोजगार और विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तथापि, कच्ची खालों व चमड़ियों की प्राकृतिक संपन्नताओं तथा विशाल मानव संसाधन जैसे तुलनात्मक लाभों के बावजूद, विश्व चमड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है। विश्व व्यापार में भारतीय चमड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न विषयों का निवारण करने की आवश्यकता होगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्ची सामग्री के संशुद्ध तथा स्थायी आधार का निर्माण, अवसंरचना सृजन, निवेश संवर्धन, औद्योगिकी अंतरण, ब्रांडिंग तथा अन्तरराष्ट्रीय छवि निर्माण और निर्यात के लिए विपणन शामिल है।

2. उपर्युक्त रणनीति के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए, चमड़ा क्षेत्र का विकास करने हेतु निम्नलिखित संरचना के साथ एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है :-

1. सदस्य (उद्योग), योजना आयोग	अध्यक्ष
2. सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
3. सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
4. सचिव, पशु-पालन विभाग	सदस्य
5. सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय	सदस्य
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
7. सचिव, कृषि मंत्रालय	सदस्य
8. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
9. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	सदस्य
10. निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान	सदस्य
11. सचिव, उद्योग, तमिलनाडु	विशेष आमंत्रित
12. सचिव, उद्योग, पश्चिम बंगाल	विशेष आमंत्रित
13. सचिव, उद्योग, केरल	विशेष आमंत्रित
14. सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश	विशेष आमंत्रित
15. सचिव, उद्योग, हरियाणा	विशेष आमंत्रित
16. संयुक्त सचिव (चमड़ा)	सचिव
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	

समिति किसी अन्य व्यक्ति को भी आमंत्रित कर सकती है।

3. अन्तर-मंत्रालयी समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :-

- (i) चमड़ा क्षेत्र के विकास हेतु एक व्यापक रणनीति तैयार करने की दृष्टि से भारतीय चमड़ा उद्योग की शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण करना;

- (ii) कच्ची सामग्री का एक सशक्त तथा स्थायी आधार बनाने के लिए उपायों का सुझाव देना;
- (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
- (iv) चमड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य विधि दृष्टिकोण अपनाने हेतु रणनीतियाँ तैयार करना;
- (v) चमड़ा और संबद्ध गैर-चमड़ा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना।

4. समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार करेगी और ऐसी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझती हो।

5. समिति से संबंधित कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अन्तर-मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और सचिवों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन. एन. प्रसाद
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2006

सं. एफ. 9-10/2004-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एल.एन.एम. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु नई श्रेणी के तहत तीन वर्ष की समीक्षा की शर्त आधार पर एतद्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित करती है। भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थान

को किसी तरह का योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

संकल्प

सं. एफ. 20-4/2003-ए एण्ड ए--एशियाटिक सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 5-11 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 जनवरी 2005 के ज्ञापन के जरिए गठित एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के आयोजना बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :--

1. प्रो. सुभद्र कुमार सेन,
आजीवन सदस्य,
एशियाटिक सोसायटी,
कोलकाता।
2. श्री विश्वनाथ बनर्जी,
अध्यक्ष,
एशियाटिक सोसायटी परिषद्,
कोलकाता।

उपर्युक्त नियुक्ति इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

आयोजना बोर्ड के कार्यकलापों को शासित करने वाले नियम वही होंगे जो दिनांक 25 जून, 1984 (फा. सं. 8-16/84-सी एच-डेस्क) के सामान्य कानूनी नियम 472 (ई) के जरिए अधिसूचित किए गए हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 13th February 2006

RESOLUTION

No. F.4/(13)/2004-Hindi.—Consequent upon his ceasing to be a member of the Lok Sabha with effect from 23rd December 2005 afternoon, Shri Manoj Kumar has ceased to be a member of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs with effect from 23rd December 2005 afternoon.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

P. GOPALAKRISHNAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 6th January 2006

RESOLUTION

No. 5(1)/2005-Leather.—The Leather Industry occupies a prominent place in the Indian economy in view of its substantial export earnings, employment and growth potential. However, despite comparative advantages such as natural endowments of raw hides and skins and vast human resource, the share of India in the global leather trade is merely 3%. In order to enhance the competitiveness of the Indian leather industry in global trade, various issues would need to be addressed, which include *inter alia*, building strong and sustainable raw material base, infrastructure creation, investment promotion, technology transfer, branding and international image building and marketing for export.

2. The above strategy necessitates coordination between various Central Ministries/Departments as well as State Governments. In order to facilitate this process, it has been decided to constitute an Inter-Ministerial Committee for development of the leather sector with the following composition :—

- | | |
|--|----------|
| 1. Member (Industry),
Planning Commission | Chairman |
| 2. Secretary, DIPP | Member |
| 3. Secretary,
Department of Commerce | Member |

- | | |
|--|-----------------|
| 4. Secretary, Department of Animal Husbandry | Member |
| 5. Secretary, Ministry SSI | Member |
| 6. Secretary, Department of Rural Development | Member |
| 7. Secretary, Ministry of Agriculture | Member |
| 8. Secretary, Ministry of Food Processing Industries | Member |
| 9. Director General, Council of Scientific & Industrial Research | Member |
| 10. Director, Central Leather Research Institute | Member |
| 11. Secretary Industry, Tamil Nadu | Special Invitee |
| 12. Secretary Industry, West Bengal | Special Invitee |
| 13. Secretary Industry, Kerala | Special Invitee |
| 14. Secretary Industry, U.P. | Special Invitee |
| 15. Secretary Industry, Haryana | Special Invitee |

16. Joint Secretary (Leather) DIPP Secretary
The Committee may invite any other person.

3. The Terms of Reference of the Inter-Ministerial Committee will be as follows :—

- (i) Analyse the strength and weaknesses of the Indian leather industry with a view to evolving a comprehensive strategy for the development of the leather sector;
- (ii) Recommend measures for building a strong and sustainable raw material base;
- (iii) Recommend measures for technology upgradation;
- (iv) Formulate strategies for adopting a mission mode approach for enhancing the competitiveness of the leather sector;
- (v) Formulate strategies for increasing investments in the leather and related non-leather sectors.

4. The Committee will devise its own procedures and may appoint Sub-Committees, as it may consider necessary.

5. The Committee will be serviced by the Department of Industrial Policy & Promotion.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Members, Special Invitees and Secretary of the Inter-Ministerial Committee.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. N. PRASAD
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 3rd February 2006

No. F. 9-10/2004-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the LNM Institute of Information Technology, Jaipur as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act under De Novo category with immediate effect subject to a review after three years. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non-Plan grants to the Institute.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 31st January 2006

RESOLUTION

No. F.20-4/2003-A&A.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of The Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984), the Central Government hereby appoints the

following as Members on the Planning Board of the Asiatic Society, Kolkata constituted vide Resolution dated 18.1.2005 published in the Gazette of India dated February 5-11, 2005 :—

1. Prof. Subhadra Kr. Sen,
Life Member,
Asiatic Society,
Kolkata.
2. Shri Biswanath Banerjee,
President,
Asiatic Society Council,
Kolkata.

2. The above appointment will be effected from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

3. The rules governing the activities of the Planning Board will be the same as notified vide GSR 472 (E) dated the 25th June, 1984 (No. F.8-16/84-CH-Desk).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India.

K. JAYAKUMAR
Jt. Secy.